अध्याय-2

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

2.1 परिहार्य वित्तीय भार

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भू-स्वामियों के संवैधानिक अधिकार और भूमि अधिग्रहण/भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एल.ए./एल.ए.आर.आर.) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक सड़क परियोजना में गैर-अधिगृहीत भूमि का उपयोग करने और माननीय न्यायालय के निर्देशों के बाद ही इसके अधिग्रहण ने भू-स्वामियों को लंबी अवधि के लिए बिना किसी मुआवजे के उनकी भूमि से वंचित रखा और इसके कारण ₹ 3.66 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार भी पड़ा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानूनी प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 8 के अनुसार, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि को चिह्नित किया जाना और मापा जाना अनिवार्य है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत, ऐसी भूमि का उपयोग हकदार व्यक्तियों को भूमि के सभी हितों के मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

शहरी संपदा विभाग, हरियाणा सरकार ने ग्राम खेड़की दौला के पास द्वारका टाउनशिप (दिल्ली) को राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से जोड़ने वाली 150 मीटर चौड़ी परिधि सड़क (सड़क परियोजना) विकसित करने के लिए गुरुग्राम में 64.62 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की (जनवरी 2008)। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा की गई थी (मार्च 2008) और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत 63.84 एकड़[1] भूमि के लिए ₹ 52.90 करोड़[2] का अवार्ड घोषित किया गया (सितंबर 2008)।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम के जोनल प्रशासक की लेखापरीक्षा से पता चला (नवंबर 2022) कि उपर्युक्त सड़क परियोजना के लिए 63.84 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करते समय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुरुग्राम[3] के धनवापुर गांव में सड़क निर्माण के लिए तीन कनाल[4] (0.375 एकड़) भूमि का उपयोग अधिग्रहण के बिना और भू-स्वामियों को मुआवज़ा दिए बिना किया था। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम में सेक्टर 99 से 115 में सेक्टर सड़कों के लिए वर्ष 2009-10 में की गई भूमि अधिग्रहण की अनुवर्ती प्रक्रिया के दौरान भी इस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था।

---

1 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत फील्ड स्टाफ द्वारा मौके पर मापी गई।

2 ₹ 60 लाख प्रति एकड़ और अन्य प्रभार जैसे संरचना का मुआवजा, अनिवार्य अधिग्रहण आदि।

3 खसरा संख्या 40//13/2मिन (0-13) और 14मिन (2-7)

4 एक कनाल = 605 वर्ग गज; एक एकड़ = 8 कनाल

पीड़ित भू-स्वामियों ने मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (एलएआरआर अधिनियम) के अंतर्गत मुआवजे के लिए अनुरोध किया (दिसंबर 2018)। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भू-स्वामियों के अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस तथ्य के बावजूद कि उसके द्वारा गैर-अधिगृहीत भूमि का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया था। इस निष्क्रियता के कारण भू-स्वामियों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की (अप्रैल 2019)। माननीय न्यायालय ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम के अंतर्गत उपर्युक्त गैर-अधिगृहीत भूमि के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया (अक्तूबर 2021)। इसके बाद, एक समिति[5] ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संशोधित नीति (8 मार्च 2019)[6] की क्लॉज ए (ii) के अनुसार 3-कनाल (0.375 एकड़) भूमि ₹ 3.97 करोड़[7] में खरीदने की सिफारिश की (अक्तूबर 2021)। भू-स्वामियों द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पक्ष में ₹ 3.97 करोड़ के भुगतान पर निष्पादित बिक्री विलेख (अगस्त 2023) के माध्यम से भूमि औपचारिक रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी गई।

इस प्रकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा एक सड़क परियोजना में गैर-अधिगृहीत भूमि का उपयोग भू-स्वामियों के संवैधानिक अधिकार और भूमि अधिग्रहण/भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया और माननीय न्यायालय के निर्देशों के बाद ही इसका अधिग्रहण किया गया, जिससे न केवल भू-स्वामियों को बिना किसी मुआवजे के उनकी भूमि से वंचित रखा गया, बल्कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर ₹ 3.66 करोड़ (₹ 3.97 करोड़ - ₹ 0.31 करोड़[8]) का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ा।

प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया (नवंबर 2024) कि साइट पर विकास कार्यों के निष्पादन के दौरान, यह पता चला कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की परियोजना को पूरा करने के लिए आस-पास की गैर-अधिगृहीत भूमि के कुछ हिस्से का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक था। नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अनुसार लंबी अधिग्रहण प्रक्रिया से बचने के लिए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अवसंरचना परियोजनाओं के लिए गैर-अधिगृहीत भूमि की खरीद के संबंध में एक नीति बनाई और तदनुसार ₹ 3.97 करोड़ का भुगतान किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को साइट पर विकास कार्य के दौरान ही इस तथ्य की जानकारी थी कि गैर-अधिगृहीत भूमि का उपयोग सड़क परियोजना में किया जाना था। तथापि, उसने अधिग्रहण के बिना ही इस भूमि का उपयोग सड़क परियोजना

---

5 गैर-अधिगृहीत भूमि के हिस्से के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए क्षेत्रीय प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम, डीटीपी/एटीपी, गुरुग्राम, एसई-I, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम और संपदा अधिकारी-I, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम शामिल थे।

6 भू-स्वामी की भूमि से सटी/संलग्न भूमि के लिए घोषित अभिनिर्णय (अवार्ड) या उस राजस्व संपदा की कलेक्टर दर, जिसमें भूमि स्थित है, में से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर भूमि की अद्यतन लागत का भुगतान किया जाएगा।

7 प्रति एकड़ ₹ 4.48 करोड़ की दर से गणना की गई, जिसमें 100 प्रतिशत अनुग्रह राशि (सोलेशियम) और 1,094 दिनों के लिए 12 प्रतिशत ब्याज शामिल है।

8 आनुपातिक लागत अर्थात ₹ 52.90 करोड़/63.84 एकड़ * 0.375 एकड़।

में कर लिया तथा ग्यारह वर्षों की अत्यधिक देरी के बाद और माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही इसे खरीदा।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के पास भेजा गया था (मई 2024); उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार, भूमि अधिग्रहण/भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम के प्रावधानों तथा भू-स्वामियों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए अधिग्रहण के बिना सड़क परियोजना में निजी भूमि के उपयोग के लिए उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे।

2.2 विस्थापितों के लिए नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण एक विस्थापित दावेदार को बहुत कम दर पर प्लॉट आबंटित करने पर ₹ 1.97 करोड़ की हानि हुई, जिसका अनुचित लाभ अंततः एक गैर-विस्थापित व्यक्ति को प्लॉट के आबंटन के चार महीने के भीतर उसके हस्तांतरण/पुनःहस्तांतरण की अनुमति देकर दिया गया।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने उन विस्थापितों[9] को प्लॉट प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की (सितंबर 1987) जिनकी भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत की गई थी। तदनुसार, विस्थापितों को विस्थापितों के दावों/कोटे के विरुद्ध आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों के उत्तर में संबंधित संपदा अधिकारी को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था, जिसके साथ अवार्ड, नकल जमाबंदी या रजिस्ट्री की एक प्रति और प्लॉट की लागत के 10 प्रतिशत के बराबर बयाना राशि भी जमा करनी थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नीति दिशानिर्देशों (अगस्त 2016) की क्लॉज 15 में यह निर्धारित किया गया कि किसी विस्थापित व्यक्ति, जिसने पहले विस्थापित नीति के अंतर्गत प्लॉट के लिए आवेदन किया था और जिसका आवेदन या तो निर्णय के लिए लंबित था या उसे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन न्यायालय/प्राधिकरण/फोरम द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया था, को नए विज्ञापन के उत्तर में प्लॉट के लिए आवेदन करने की सलाह दी जानी चाहिए। उपर्युक्त नीति दिशानिर्देशों में मई 2018 में संशोधन किया गया था, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त, क्लॉज 15ए और क्लॉज 19 शामिल थी, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- **क्लॉज 15ए** में प्रावधान है कि यदि कोई विस्थापित व्यक्ति नए विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन करता है, तो प्लॉट की कीमत नए विज्ञापन में विज्ञापित दरों के अनुसार ही ली जाएगी। तथापि, यदि विस्थापित की पात्रता निर्धारित करने के बावजूद पूर्ववर्ती विज्ञापन के आधार पर प्लॉट आबंटित नहीं किया जा सका, तो उस विज्ञापन के अनुसरण में विस्थापित द्वारा आवेदन के समय प्रचलित मूल्य, आबंटन तिथि तक 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित, लिया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया था कि पात्रता पर तभी विचार/निर्धारण किया जाएगा जब विस्थापित व्यक्ति ने लागू नीति के अनुसार सभी औपचारिकताएं/शर्तें पूरी कर ली हों और उनसे संतुष्ट हो।

[9] वे व्यक्ति जिनकी भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत की गई थी।

- **क्लॉज 19** में प्रावधान है कि आबंटित प्लॉट को आबंटन-पत्र जारी होने की तिथि से पांच वर्ष तक बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2023) कि एक भू-स्वामी वर्ष 1992 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 11 कनाल[10] 8 मरला[11] (गांव रामगढ़, तहसील और जिला पंचकुला) कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरूद्ध विस्थापित कोटे के अंतर्गत एक कनाल[12] के प्लॉट के आबंटन के लिए पात्र था। भू-स्वामी ने विस्थापित कोटे के अंतर्गत प्लॉट के आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि मार्च 2006 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विस्थापितों की योजना के विज्ञापन से पहले फरवरी 2006 में उनकी मृत्यु हो गई थी। भू-स्वामी की विधवा और दो अन्य लोगों सहित तीन व्यक्तियों, जिनमें से प्रत्येक के पास मृतक भू-स्वामी से अलग 'वसीयत' हैं, द्वारा विस्थापित दावे के विरुद्ध प्लॉट के आबंटन के लिए आवेदन करने पर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के शीर्ष अपीलीय निकाय ने निर्णय लिया (फरवरी 2008) कि तीनों आवेदकों को संयुक्त रूप से प्लॉट आबंटित किया जाएगा। तथापि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया (जुलाई 2009), जिसमें भू-स्वामी की विधवा को छोड़कर केवल दो आवेदकों को ही प्लॉट का अधिकार दिया गया। इस आदेश को मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अदालत में चुनौती दी गई (जुलाई 2009)।

अपर जिला न्यायाधीश, पंचकुला की अदालत ने विस्थापित कोटे के अंतर्गत प्लॉट के लिए उपर्युक्त तीनों आवेदकों के अधिकार को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया (मार्च 2019) कि मृतक भू-स्वामी के कानूनी उत्तराधिकारी विस्थापित कोटे के अंतर्गत प्लॉट के हकदार हैं, लेकिन यह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की विस्थापितों की नीति के अनुसार ही होगा। इसके बाद, मृतक भू-स्वामी के एक बेटे ने मृतक भू-स्वामी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपने नाम पर प्लॉट के आबंटन के लिए अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत किया (मार्च 2021)। संपदा अधिकारी, पंचकुला ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संशोधित नीति दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 11 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर के साथ वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 66,000 प्रति वर्गमीटर की बजाय 2006 में प्रचलित ₹ 19,190 प्रति वर्गमीटर की दर पर 420 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले एक प्लॉट के आबंटन हेतु मृतक भू-स्वामी के पुत्र के पक्ष में आबंटन-पत्र जारी किया (अप्रैल 2021)। इसके अतिरिक्त, संशोधित नीति दिशानिर्देशों की क्लॉज 19 के उल्लंघन में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने उक्त आबंटित प्लॉट को दो बार, पहले जून 2021 में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर और उसके बाद अगस्त 2021 में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, हस्तांतरित करने की अनुमति दी।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपने स्वयं के नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया, जिसके कारण दावेदार विस्थापित को बहुत कम दर पर प्लॉट आबंटित करने पर ₹ 1.97 करोड़[13] की हानि हुई, जिसका लाभ अंततः एक गैर-विस्थापित व्यक्ति को विस्थापित कोटे के अंतर्गत आबंटित प्लॉट को आबंटन के चार महीने के भीतर उसके हस्तांतरण/पुनःहस्तांतरण की अनुमति देकर दिया गया।

---

10 कृषि भूमि के लिए एक कनाल 605 वर्ग गज के बराबर होता है।

11 एक मरला 30 वर्ग गज के बराबर होता है।

12 शहरी क्षेत्रों में एक कनाल 500 वर्ग गज के बराबर होता है।

13 ₹ 66,000 - ₹ 19,190 (प्रति वर्गमीटर) x 420 वर्गमीटर।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2025) कि अगस्त 2016 और मई 2018 की नीतियों के अनुसार, विस्थापित व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के समय प्रचलित कीमतों को 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर के साथ प्रभारित किया जाना था। इसलिए, कोई हानि नहीं हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संशोधित नीति दिशानिर्देशों की क्लॉज 15ए के अनुसार, प्लॉट का आबंटन ₹ 66,000/- प्रति वर्गमीटर की प्रचलित दर पर किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, उत्तर में विस्थापितों के लिए संशोधित नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, विस्थापित कोटे के अंतर्गत आबंटित प्लॉट के हस्तांतरण/पुनःहस्तांतरण की अनुमति देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

सिफारिश: राज्य सरकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के वित्तीय हित से समझौता करने और एक गैर-विस्थापित व्यक्ति को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए विस्थापितों की नीति दिशानिर्देशों के उल्लंघन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे।

वन विभाग

2.3 निवल वर्तमान मूल्य की गलत मांग

विभाग द्वारा विद्यमान दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निवल वर्तमान मूल्य की गलत मांग और परिवर्तित वन भूमि के स्वामित्व मूल्य की कोई मांग न करने के कारण राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में निधियों की वसूली में ₹ 22.63 करोड़ की महत्वपूर्ण कमी आई।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन संरक्षण नियम, 2003 (इसके बाद दिशानिर्देश के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के प्रभावी एवं पारदर्शी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों की पुस्तिका जारी की (मार्च 2019)। ये दिशानिर्देश गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को रेखांकित करते हैं।

दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 में प्रावधान है कि प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) के लिए प्राप्त निधियों के अतिरिक्त, गैर-वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित की जा रही वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) भी वन सुरक्षा, संरक्षण उपायों और संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से वसूल किया जाना है। इसके अतिरिक्त, पैरा 3.4 में प्रावधान है कि यदि परिवर्तित वन भूमि का क्षेत्र किसी वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है तो लागू निवल वर्तमान मूल्य सामान्य निवल वर्तमान मूल्य का पांच गुना होगा। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में 'लागत-लाभ विश्लेषण (सीबीए)' करना अनिवार्य है जहां प्रस्तावित परिवर्तित वन भूमि पहाड़ियों पर स्थित है और इसमें पांच हेक्टेयर से अधिक वन भूमि शामिल है। 'लागत-लाभ विश्लेषण' के बाद, परिवर्तित

वन भूमि के स्वामित्व मूल्य के रूप में अतिरिक्त लागत[14] उपयोगकर्ता एजेंसी से वसूल की जानी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अक्तूबर 2022)[15] कि वन विभाग, हरियाणा सरकार (विभाग) ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) द्वारा 440 किलोवोल्ट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) सब-स्टेशन नग्गल (बरवाला) से पंचकुला और पिंजौर में 220 किलोवोल्ट लाइनों के स्थापन के लिए वन भूमि के डायवर्जन के संबंध में अनुमोदन के लिए सिफारिश की (जून 2020)। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (सितंबर 2020) और उसके बाद अंतिम अनुमोदन (दिसंबर 2021) प्रदान किया। इस परियोजना में उक्त ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के लिए पंचकुला के खोल ही-रैतान वन्यजीव अभयारण्य में 46.375 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन शामिल था। विभाग ने उपर्युक्त वन भूमि की कुल डायवर्जन लागत (प्रतिपूरक वनरोपण, निवल वर्तमान मूल्य आदि सहित) के रूप में ₹ 21.96 करोड़ की मांग की, और इसे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जमा किया गया (अक्तूबर 2021)। इस राशि में वन्यजीव अभयारण्य भूमि के डायवर्जन के लिए देय ₹ 20.57 करोड़[16] (सामान्य निवल वर्तमान मूल्य का पांच गुना) के बजाय केवल ₹ 4.11 करोड़[17] का निवल वर्तमान मूल्य शामिल था। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों में दिए गए अनुसार 'लागत-लाभ विश्लेषण' भी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा वन भूमि के ₹ 6.17 करोड़ (निवल वर्तमान मूल्य का 30 प्रतिशत) के स्वामित्व मूल्य की मांग भी नहीं की गई थी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में निवल वर्तमान मूल्य की गलत मांग और परिवर्तित वन भूमि के स्वामित्व मूल्य की कोई मांग न करने के कारण, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में निधियों की वसूली में ₹ 22.63 करोड़[18] की महत्वपूर्ण कमी आई।

मंडलीय वन अधिकारी (प्रादेशिक) मोरनी-पिंजौर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2024) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए निवल वर्तमान मूल्य की मांग उपयोगकर्ता एजेंसी से की गई है, जिसकी वसूली अभी नहीं हुई है। यह भी बताया गया कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से ₹ 22.63 करोड़ जमा करने के लिए पुनः अनुरोध किया गया है (अगस्त 2025)।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वन एवं वन्य जीव विभाग के पास भेजा गया था (मार्च और मई 2024); उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

---

14 सिंचाई, जलविद्युत, रेलवे, सड़कों, पवन ऊर्जा और पारेषण लाइनों तथा खनन आदि जैसी परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई वन भूमि के वापस आने की संभावना नहीं है और यह उपयोगकर्ता एजेंसियों के कब्जे में ही रहती है। इसलिए, विपथित वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य या जिले में आसपास के क्षेत्र के बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत वनों की हानि के कारण होने वाली पर्यावरणीय लागतों के अतिरिक्त "वन भूमि का कब्जा मूल्य" के रूप में लागत घटक के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।

15 मंडलीय वन अधिकारी (प्रादेशिक) मोरनी-पिंजौर के अभिलेखों की जांच के दौरान।

16 ₹ 4,11,34,625*5= ₹ 20,56,73,125

17 ₹ 8,87,000 प्रति हेक्टेयर * 46.375 = ₹ 4,11,34,625

18 ₹ 20.57 करोड़ + ₹ 6.17 करोड़ - ₹ 4.11 करोड़ (पहले से भुगतान किया गया) = ₹ 22.63 करोड़।

मानव संसाधन विभाग और वित्त विभाग

2.4 राज्य के खजाने पर परिहार्य वित्तीय भार

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को समय पर भुगतान करने में संबंधित 191 मांगकर्ता संस्थाओं के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की अक्षमता के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के भुगतान में विलंब हुआ और जुर्माना लगाया गया, जिससे अंततः राज्य के खजाने पर ₹ 8.29 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार पड़ा।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 38 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 3 के अनुसार, किसी भी प्रतिष्ठान के नियोक्ता को प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास भविष्य निधि अंशदान जमा करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (अधिनियम) की धारा 7क्यू में प्रावधान है कि नियोक्ता देरी के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और अधिनियम की धारा 14बी भविष्य निधि आयुक्त को भुगतान में चूक के लिए नियोक्ता पर जुर्माना लगाने का प्राधिकार देती है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) को हरियाणा की सभी सरकारी संस्थाओं को संविदा कर्मचारी प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था (अक्तूबर 2021)। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से संविदा कर्मचारियों की तैनाती के लिए हरियाणा संसाधन विभाग (एचआरडी) अर्थात हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के प्रशासनिक विभाग, हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों की तैनाती नीति, 2022 (नीति) नामक एक नीति तैयार की, जो 01 अप्रैल 2022[19] से लागू थी। नीति के पैराग्राफ 5.4 और 5.5 के अनुसार, प्रत्येक मांगकर्ता विभाग को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पोर्टल पर जारी किए गए चालानों के भुगतान के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपेक्षित है। यदि तैनात कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक नहीं किया जाता है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड उस मांग करने वाले संगठन से कर्मचारियों को वापस लेने और/या ₹ 50 प्रतिदिन प्रति कर्मचारी की दर से जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।

संविदा कर्मचारियों की मांग हेतु मांग-पत्र जारी करने, उपस्थिति दर्ज करने और तैनात कर्मचारियों के लिए मासिक चालान जारी करने सहित पूरी प्रक्रिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित है। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति जमा करने और अपलोड करने के बाद, पोर्टल पर मासिक चालान स्वचालित रूप से तैयार हो जाते हैं। तदनुसार, मांगकर्ता सरकारी संस्थाओं से मासिक चालान का भुगतान प्राप्त करने के बाद, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, तैनात कर्मचारियों को उपस्थिति के अनुसार मासिक वेतन का भुगतान करता है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मासिक अंशदान करता है।

[19] राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2022 को अधिसूचित।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने सभी प्रशासनिक सचिवों और सभी मांगकर्ता विभागों/सरकारी संस्थाओं के प्रमुखों से अनुरोध किया (अगस्त 2022 में) कि वे संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर सभी संविदा कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा का सही विवरण प्रस्तुत करें, और कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा भुगतान जमा करने में देरी के कारण हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पर लगाया गया कोई भी जुर्माना संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, पंचकुला के कार्यालय में लेखापरीक्षा (अगस्त-सितंबर 2023) के दौरान, यह पाया गया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने 191 मांगकर्ता सरकारी संस्थाओं के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान भेजने में 12 से 530 दिनों तक की देरी के कारण, जुलाई 2022 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ₹ 8.29 करोड़ के जुर्माने का भुगतान किया था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1*** में विस्तृत रूप से बताया गया है तथा ***तालिका 2.1*** में संक्षेप में बताया गया है।

तालिका 2.1: विलंब और जुर्माने के भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी

भुगतान किए गए प्रेषण का माह	भुगतान की गई जुर्माने की राशि (₹ लाख में)	विलंबित अवधि (दिनों में)	
		न्यूनतम	अधिकतम
जुलाई 2022	169.08	13	142
अक्तूबर 2022	150.27	13	197
नवंबर 2022	82.80	25	239
दिसंबर 2022	56.73	15	350
जनवरी 2023	47.46	13	289
फरवरी 2023	30.83	14	318
मार्च 2023	39.71	17	352
अप्रैल 2023	46.01	16	381
मई 2023	31.00	15	411
जून 2023	51.22	19	442
जुलाई 2023	63.70	16	473
अगस्त 2023	38.26	15	502
सितंबर 2023	22.22	12	530
कुल	**829.29**		

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भुगतान किया गया जुर्माना, बाद में संबंधित मांगकर्ता सरकारी संस्थाओं के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से आगामी माह के चालान में जुर्माने की राशि जोड़कर वसूल किया गया। कुल जुर्माने में से, ₹ 4.69 करोड़ (56.57 प्रतिशत) केवल नौ प्रमुख चूककर्ता संगठनों/विभागों द्वारा वहन किए गए, जिनकी राशि ₹ 0.20 करोड़ से ₹ 1.52 करोड़ के बीच थी, जैसा कि ***तालिका 2.2*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: प्रमुख चूककर्ता संगठनों/विभागों द्वारा वहन किए गए जुर्माने के विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	जुर्माने की राशि (₹ लाख में)
1	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	152.33
2	स्वास्थ्य	102.50
3	सिंचाई एवं जल संसाधन	57.58
4	प्राथमिक शिक्षा	31.98
5	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	29.73
6	शहरी स्थानीय निकाय	26.84
7	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	25.41
8	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	21.97

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा तैनात कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा करने में देरी के मुख्य कारण संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर कर्मचारियों के विवरण को गलत ढंग से अद्यतन करना और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को मासिक भुगतान में देरी थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हरियाणा सरकार ने अपने 17 मार्च 2023 के परिपत्र के माध्यम से नीति के पैराग्राफ 5.5 को हटा दिया था, जिसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को चूककर्ता संगठनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया था। इसलिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पास चूककर्ता संस्थाओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं बचा, सिवाय इसके कि वह समय-समय पर उनसे समय पर भुगतान करने का अनुरोध करता रहे।

इस प्रकार, संबंधित 191 मांगकर्ता संस्थाओं के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को समय पर भुगतान न करने में अक्षमता के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान देरी से हुआ और इसके परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया गया, जिससे अंततः राज्य के खजाने पर ₹ 8.29 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार पड़ा। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बताया (अप्रैल 2025) कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को भुगतान में देरी के मुख्य कारण बजट की अनुपलब्धता और संविदा कर्मियों द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने सभी सरकारी संस्थाओं को निर्देश जारी किए (नवंबर 2024) कि वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियोजित सभी संविदा कर्मचारियों के संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर कर्मचारी भविष्य निधि डेटा के सही विवरण को अद्यतन करना सुनिश्चित करें और प्रत्येक माह की 7 तारीख तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को भुगतान करें; यदि किसी विभाग के पास बजट संबंधी कोई समस्या है तो उसे वित्त विभाग के साथ मामला उठाना चाहिए।

लेखापरीक्षा स्वीकार करती है कि राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की तैनाती नीति, 2022 में पैराग्राफ 5.5 को शामिल करके संशोधन को अधिसूचित किया (मई 2025), जिसके अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को दोषी संगठनों/विभागों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया, जिसे पहले मार्च 2023 में हटा दिया गया था।

सिफारिश: राज्य सरकार, तैनात कर्मचारियों का विवरण अद्यतन न करने और राज्य के खजाने पर परिहार्य वित्तीय भार डालने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित संगठन/विभाग द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि आदि जैसी सांविधिक देय राशियों के भुगतान हेतु बजट मांग समय पर प्रस्तुत की जाती है और उन्हें समय पर जारी भी की जाती है।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

2.5 अपूर्ण कार्यों पर निष्फल व्यय

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत में चार कार्य चार से पांच वर्षों के बाद भी अपूर्ण रहे, जिससे ₹ 25.86 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित (अक्तूबर 2009) हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) लोक निर्माण से संबंधित विभिन्न चिंताओं को दूर करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जैसे कि कार्यों को समय पर पूरा करना, कार्यक्रमों का पारदर्शी और लागत प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन तथा सबसे उपयुक्त सामग्री, डिजाइन और निर्माण प्रौद्योगिकियों तथा प्रबंधन पद्धतियों का उपयोग करना, आदि। संहिता के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

- पैरा 10.1.3 में यह प्रावधान है कि किसी भी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय, भूमि की उपलब्धता सहित, क्षेत्र की स्थिति का पता लगाने के लिए साइट का निरीक्षण किया जाना चाहिए। अनुमान इच्छित उद्देश्य के लिए एक लागत-प्रभावी प्रस्ताव होना चाहिए और यथासंभव सटीक होना चाहिए।
- पैरा 9.5.1 में यह प्रावधान है कि किसी विस्तृत अनुमान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति का तात्पर्य यह है कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से सुदृढ़ है, विनिर्देशन इच्छित सेवा के लिए उपयुक्त हैं तथा अनुमान पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर वास्तविक है।
- पैरा 9.3.7 और 9.3.10 में यह प्रावधान है कि जहां व्यय में प्रशासनिक अनुमोदन (एए) से 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की संभावना हो, वहां संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक है। संशोधित अनुमान के लिए मामला यथाशीघ्र, अधिमानतः संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता की जानकारी होने के एक महीने के भीतर भेजा जाना चाहिए।

- पैरा 16.37.1 में, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधान है कि समय की अधिकता के परिणामस्वरूप परियोजना लागत और संविदात्मक दावे बढ़ सकते हैं और सुविधा के उपयोग में और देरी हो सकती है। समय की अधिकता की घटनाओं को कम करने के लिए, (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि साइट की स्थितियां निविदा दस्तावेज में वर्णित स्थितियों से बहुत भिन्न नहीं हैं, साइट का गहन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए; (ii) कार्य शुरू होने से पहले साइट ठेकेदार को सौंप दी जानी चाहिए; (iii) परियोजना को समग्र रूप से व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

लोक निर्माण विभाग (विभाग) के चार मंडलों[20] के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण चार कार्य अपूर्ण रह गए तथा उन पर ₹ 25.86 करोड़ का व्यय निष्फल रहा तथा इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) जलभराव की संभावना वाले स्थल के कारण अपूर्ण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन

राज्य सरकार ने गांव नलवी, बसंतपुर, कुरुक्षेत्र में ₹ 11.10 करोड़ की लागत से एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2019)। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने ₹ 7.78 करोड़ के विस्तृत अनुमान हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2019)। यह कार्य एक ठेकेदार को ₹ 7.57 करोड़ की लागत से 18 महीने (11 जनवरी 2021 तक) की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ सौंपा गया था (जून 2019)।

ठेकेदार ने कार्यकारी अभियंता को सूचित किया (जुलाई 2019) कि यह स्थल एक निचला जलभराव क्षेत्र था जहां बारिश के दौरान जलभराव की संभावना रहती थी और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग से मिट्टी भरने का अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कार्यकारी अभियंता ने मिट्टी भरने के लिए ₹ 25.03 लाख का अनुमान जून 2023 में ही प्रस्तुत किया, जो कि अनुमोदित नहीं हुआ।

ठेकेदार ने जुलाई 2022 तक ₹ 4.02 करोड़ का कार्य पूरा कर लिया था (नवंबर 2022 में भुगतान किया गया), उसके बाद कार्य में कोई प्रगति या भुगतान नहीं हुआ। साइट की बाधाओं को दूर करने के बजाय, प्रमुख अभियंता ने ठेकेदार को मार्च 2023 तक का समय विस्तार प्रदान किया (अगस्त 2022)। ठेकेदार ने दोहराया (सितंबर 2022) कि यदि मिट्टी भरने का कार्य तीन वर्ष पहले किया गया होता तो कार्य मूल समय-सीमा के भीतर पूरा हो सकता था।

इस प्रकार, समय पर साइट की बाधाओं को दूर करने में विभाग की अक्षमता के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण पूरा नहीं हो सका, जिससे ₹ 4.02 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, साथ ही अभी तक इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी, जैसा कि नीचे दिए गए फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:

---

[20] प्रांतीय मंडल-2, कुरुक्षेत्र (दिसंबर 2023), प्रांतीय मंडल, रेवाड़ी (दिसंबर 2018 और जनवरी 2024), प्रांतीय मंडल, पानीपत (अक्तूबर 2023) और प्रांतीय मंडल-2, कैथल (अक्तूबर 2023)।

13 अगस्त 2025 तक अपूर्ण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन को दर्शाने वाला फोटोग्राफ
(कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल-2, कुरुक्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया)

प्रमुख अभियंता ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2024) कि अनुमान तैयार करने से पहले साइट का सर्वेक्षण किया गया था। परियोजना स्थल मुख्य रूप से मारकंडा नदी बेसिन के भीतर स्थित था, जिस कारण यह क्षेत्र भारी बारिश के दौरान बाढ़ और लंबे समय तक जलभराव के कारण संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी अभियंता ने सूचित किया (अगस्त 2025) कि मिट्टी भरने का कार्य ₹ 20 लाख की लागत से अप्रैल 2025 में निष्पादित किया गया था और यह कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है।

यह स्पष्ट है कि मिट्टी भरने के कार्य में पांच वर्ष से अधिक की देरी के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण अपूर्ण रह गया, जिससे अपेक्षित लाभ से वंचित रहना पड़ा।

(ii) पहुंच मार्ग न बनने के कारण अपूर्ण रेलवे अंडर ब्रिज और अंडरपास

राज्य सरकार ने रेवाड़ी-नारनौल लाइन पर किलोमीटर 13/0-1 (आरडी 65,400) पर रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण के लिए ₹ 19.89 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (जून 2017) ताकि गोविंदपुरी गांव के निवासियों को अपने खेतों पर आने-जाने के दौरान दुर्घटना के जोखिम से बचाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2020) प्रस्ताव के अनुसार, इस परियोजना में रेलवे द्वारा रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा एक अंडरपास का निर्माण और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा गोविंदपुरी गांव तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण शामिल था। पहुंच मार्ग के लिए 6 कनाल 2 मरला भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित था।

रेलवे ने रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण किया, जिसके लिए प्रांतीय मंडल (भवन एवं सड़कें), रेवाड़ी ने रेलवे के पास ₹ 11.84 करोड़ जमा किए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सितंबर 2020 में उसे सौंपे[21] गए रोड अंडरपास का निर्माण भी कर दिया था। तथापि, लोक निर्माण विभाग ने गोविंदपुरी गांव तक पहुंच मार्ग के लिए भूमि की खरीद हेतु

[21] राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के निर्माणाधीन होने के कारण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने रियायतग्राही से सड़क अंडरपास का निर्माण कराने पर सहमति व्यक्त की, जिसके लिए राज्य सरकार से किसी निधि की मांग नहीं की गई थी।

ई-भूमि पोर्टल पर सितंबर 2022 में ही मांग-पत्र तैयार कर लिया था। जून 2024 तक, केवल एक कनाल भूमि के लिए ही सहमति प्राप्त हुई थी, जिससे यह संकेत मिला कि पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण पहुंच मार्ग का कार्य निष्पादित नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार, विभाग द्वारा पहुंच मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु समय पर कार्रवाई न किए जाने के कारण रेलवे अंडर ब्रिज अनुपयोगी रहा, जिससे इसके निर्माण पर किया गया ₹ 11.84 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया (जून 2024) कि शेष 5 कनाल 2 मरला भूमि के अधिग्रहण हेतु भू-स्वामियों की सहमति प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे। अपेक्षित भूमि की खरीद के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

तथापि, भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (जुलाई 2025) के अनुसार, शेष 5 कनाल 2 मरला भूमि के लिए सहमति अभी भी प्रतीक्षित थी।

(iii) अनुमान में अपर्याप्त प्रावधान के कारण अपूर्ण पुल

ग्रामीणों को अनाज मंडी, चीका (कैथल) तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से, मारकंडा नदी पर एक पुल के निर्माण सहित गांव भागल और गांव मगरान के बीच चार किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य के लिए ₹ 7.48 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया (दिसंबर 2017)। ₹ 8.13 करोड़ के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (मार्च 2019) जिसमें पुल के लिए ₹ 5.74 करोड़ का प्रावधान शामिल था। यह कार्य एक ठेकेदार को ₹ 7.58 करोड़ की करार राशि पर सौंपा गया (जून 2019), जिसके पूरा होने की समय-सीमा जनवरी 2021 थी। ठेकेदार ने जुलाई 2021 तक ₹ 8.14 करोड़ के कार्यों को निष्पादित किया और उसके बाद कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचनात्मक ड्राईंग में अवरोधक दीवारों को शामिल किए जाने के बावजूद, अनुमान में अवरोधक दीवारों का प्रावधान न होने के कारण पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका। कार्यकारी अभियंता ने अवरोधक दीवार की लागत जोड़ने के बाद अप्रैल 2023 में ₹ 13.83 करोड़ का संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत किया। राज्य सरकार द्वारा ₹ 14.90 करोड़ का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था (फरवरी 2024)।

इस प्रकार, अवरोधक दीवारों का प्रावधान शामिल किए बिना अपूर्ण अनुमान तैयार करने के कारण पुल का निर्माण निर्धारित समय में पूरा नहीं हो सका, जिससे उस पर किया गया ₹ 8.14 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया और ग्रामीणों को इसके अपेक्षित लाभ से वंचित होना पड़ा, जैसा कि नीचे दिए गए फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:

भागल और मगरान गांवों के बीच सड़क पर मारकंडा नदी पर अपूर्ण पुल को दर्शाता फोटोग्राफ
(19 अगस्त 2025 को कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल-2, कुरुक्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया)

प्रमुख अभियंता ने बताया (जून 2024) कि राज्य सरकार से फरवरी 2024 में ₹ 14.90 करोड़ का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो गया था तथा शेष कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जुलाई 2021 से कार्य रुका हुआ है और चार वर्ष बीत जाने के बाद भी, तथा नवंबर 2024 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित विस्तृत अनुमान को अनुमोदन मिलने के बाद भी, करार में वृद्धि के अनुमोदन के अभाव में कार्य पुनः आरंभ नहीं हो सका (जुलाई 2025)।

(iv) बाधाएं दूर न होने से अपूर्ण पड़ा खेल स्टेडियम

राज्य सरकार ने गांव वैसर, पानीपत में एक खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु ₹ 2.64 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया। कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल (भवन एवं सड़कें), पानीपत द्वारा जनवरी 2020 में ₹ 2.60 करोड़ का विस्तृत अनुमान प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को प्रस्तुत किया गया था, तथापि, उस पर अनुमोदन प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)। यह कार्य एक एजेंसी को ₹ 2.93 करोड़ की संविदा राशि पर दिसंबर 2021 तक पूरा करने की समय-सीमा के साथ प्रदान किया गया था (सितंबर 2020)। ठेकेदार ने ₹ 1.45 करोड़ (अगस्त 2021 में भुगतान की गई राशि) का कार्य निष्पादित किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि साइट निरीक्षण समिति (एसआईसी) ने अपनी रिपोर्ट में सूचित किया (जनवरी 2019) कि साइट सभी बाधाओं से मुक्त थी। केवल निचले इलाके की समस्या बताई गई थी और ग्राम पंचायत ने साइट को समतल करने का आश्वासन दिया था। वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज अपलोड करते समय कार्यकारी अभियंता ने भी प्रमाणित किया था (जून 2020 में) कि साइट सभी बाधाओं से मुक्त थी।

तथापि, उक्त स्थल बाधामुक्त नहीं था क्योंकि 33 किलोवोल्ट और 11 किलोवोल्ट की विद्युत लाइनें वहां से गुजर रही थी और कुछ अतिक्रमण भी थे। 33 किलोवोल्ट लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए फरवरी 2023 में ₹ 0.21 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिन्हें नवंबर 2023 में स्थानांतरित किया गया। इन बाधाओं के कारण, केवल चारदीवारी का निर्माण ही हो सका।

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार ने पहले ही 33 किलोवोल्ट लाइनों के स्थानांतरण में देरी और निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि का संदर्भ देते हुए, जिससे उद्धृत दरों पर कार्य निष्पादित करना अव्यवहारिक हो गया था, करार को समाप्त करने का अनुरोध किया था। विभाग ने अप्रैल 2024 में करार को समाप्त कर दिया।

इस प्रकार, साइट निरीक्षण समिति द्वारा गलत रिपोर्टिंग, कि साइट सभी बाधाओं से मुक्त थी, के आधार पर खेल स्टेडियम के कार्यों के निष्पादन के कारण और बाधाओं को दूर करने में देरी (33 किलोवोल्ट लाइनों का स्थानांतरण) के कारण विद्यमान करार समाप्त हो गया, खेल स्टेडियम का कार्य अपूर्ण रह गया, जिससे उस पर किया गया ₹ 1.66 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल (भवन एवं सड़कें), पानीपत ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि 33 किलोवोल्ट लाइनों को यथासमय स्थानांतरित करने की प्रत्याशा में निविदाएं आमंत्रित की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से प्रक्रिया में देरी हुई। आगे बताया गया था कि ग्राहक विभाग की मांग के अनुसार, ड्राईंग्स में परिवर्तन से अनुमानित लागत बढ़कर ₹ 4.02 करोड़ हो गई थी और शेष कार्यों के संशोधित विस्तृत अनुमान और दायरे को अंतिम रूप देने के बाद कार्य फिर से शुरू किया जाएगा।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्थल निरीक्षण समिति की रिपोर्ट (जनवरी 2019) में 33 किलोवोल्ट लाइनों के अस्तित्व का कोई उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2023 में इन लाइनों के स्थानांतरण के बाद भी, जुलाई 2025 तक कार्य फिर से शुरू नहीं हो सका।

इस प्रकार, संहिता के उल्लिखित प्रावधानों के साथ विभाग के गैर-अनुपालन के कारण, उपर्युक्त चर्चा किए गए चार कार्य, चार से पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रह गए, जिससे ₹ 25.86 करोड़[22] का सम्पूर्ण व्यय निष्फल हो गया और अपेक्षित सार्वजनिक लाभ से वंचित होना पड़ा।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के पास भेजा गया था (जुलाई 2024); उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों पर (i) ज्ञात साइट बाधाओं, अर्थात जलभराव की संभावना वाले स्थल पर मिट्टी भरने का कार्य, को दूर करने में पांच वर्ष से अधिक की अत्यधिक देरी, (ii) संबंधित निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पहुंच मार्ग के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता, (iii) प्रतिधारण दीवारों के लिए प्रावधान शामिल किए बिना अपूर्ण अनुमान तैयार करने और इसके लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने, और (iv) साइट निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा साइट स्वीकृति की गलत रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे।

[22] ₹ 4.22 करोड़ (मिट्टी भरान पर ₹ 0.20 करोड़ सहित) + ₹ 11.84 करोड़ + ₹ 8.14 करोड़ + ₹ 1.66 करोड़।

महिला एवं बाल विकास विभाग

2.6 निष्फल व्यय

प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों और पानी/बिजली आपूर्ति कनेक्शनों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 4,000 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद के कारण 2,511 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की स्थापना नहीं हुई जिससे ₹ 1.22 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में, विद्यमान आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को उन्नत करके राज्य में 4,000 प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इसके लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान इन आंगनवाड़ी केंद्रों/उन्नत प्ले स्कूलों के लिए इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर सहित विभिन्न वस्तुओं[23] की खरीद और आपूर्ति की।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2023) कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने ओडिशा की एक फर्म से एक वर्ष की प्रतिस्थापन गारंटी के साथ ₹ 4,871 प्रति इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की दर से 4,000 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश दिया (अक्तूबर 2021)। फर्म ने जनवरी 2022 तक इन इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की आपूर्ति की, जिसके लिए मार्च 2023 तक कुल ₹ 1.95 करोड़[24] का भुगतान किया गया। नवंबर 2024 तक, 4,000 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर में से केवल 1,489 को ही चालू किया जा सका। शेष 2,511 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों, पानी/बिजली आपूर्ति कनेक्शन या पानी/बिजली की फिटिंग की अनुपलब्धता के कारण चालू नहीं किए जा सके और गारंटी भी समाप्त हो गई। इसने स्पष्ट रूप से इंगित किया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वास्तविकता का पता लगाए बिना ही इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद की गई थी, क्योंकि अधिकांश प्ले स्कूलों में अपेक्षित पानी की टंकियों और पानी/बिजली आपूर्ति कनेक्शनों का अभाव था।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्ले स्कूलों में जलापूर्ति के लिए पानी की टंकियां और विद्युत मोटर उपलब्ध कराने की अनुमानित लागत के साथ पानी की टंकियों की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध फर्मों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (जनवरी 2024)। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों से भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विधिवत तैयार किए गए इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर स्थापित करने के लिए पानी की टंकियों और मोटरों की फिटिंग के लिए अनुमान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (फरवरी 2024)। मई 2024 में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और पंचायती राज विभाग ने भाग लिया और यह निर्णय लिया गया था

---

[23] स्मार्ट टेबल और कुर्सियाँ, इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर, ऑफिस टेबल, कुर्सियाँ और अलमारी, और नरम सूती हैंड टॉवल (मध्यम और बड़े)।

[24] मार्च 2022 में ₹ 170.25 लाख और मार्च 2023 में ₹ 24.36 लाख।

कि पंचायती राज विभाग जल आपूर्ति कनेक्शनों के लिए विद्युत मोटर, पानी की टंकी और आंतरिक फिटिंग की अनुमानित लागत प्रस्तुत करेगा। मुख्य अभियंता, पंचायती राज विभाग ने अनुमान प्रस्तुत किया था, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के पास विचाराधीन (नवंबर 2024) था।

इस प्रकार, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों और पानी/बिजली आपूर्ति कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 4,000 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद के परिणामस्वरूप 2,511 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर स्थापित नहीं हो पाए, जिससे ₹ 1.22 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त, प्री-स्कूल बच्चों को पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया (जून 2024) कि प्रारंभ में, वर्ष 2020-21 के दौरान पहले चरण में 1,135 प्ले स्कूलों के लिए मामला संसाधित किया गया था और शेष को वर्ष 2022-23 में दूसरे चरण में संसाधित किया जाना था, यह मानते हुए कि इन दो वर्षों में बिजली और पानी का प्रावधान किया जा सकता है। चूंकि पहले चरण में इन मदों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था, इसलिए सभी 4,000 प्ले स्कूलों के लिए मामला संसाधित किया गया था। निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने आगे बताया (दिसंबर 2024) कि वाटर प्यूरीफायर की स्थापना में देरी हुई क्योंकि बिजली कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा प्रदान किए जाने थे। इसके अतिरिक्त, जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से पानी की टंकियों की खरीद प्रक्रियाधीन थी।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह भी बताया (अगस्त 2025) कि क्षेत्रीय कार्यालयों की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 559 प्ले स्कूलों में पानी की टंकियां नहीं थी और 465 प्ले स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं थे। अन्य कमियां, जैसे उचित वाटर कनेक्शनों का अभाव, भी सूचित की गई थी।

उत्तर लेखापरीक्षा के इस तर्क की पुष्टि करता है कि प्रत्येक प्ले स्कूल में आवश्यक सहायक अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद की गई थी। इसके अतिरिक्त, इंगित किए गए 2,511 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर में से शेष 1,487 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है, और अस्थापित इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की स्थिति में गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग के पास भेजा गया था (अगस्त 2024); उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार प्रत्येक प्ले स्कूल में वास्तविकता का पता लगाए बिना इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद के लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे और यह भी सुनिश्चित करे कि शेष इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर समयबद्ध तरीके से स्थापित/कार्यात्मक किए जाएं।

2.7 बीमा प्रीमियम का अधिक भुगतान

महिला एवं बाल विकास विभाग ने "सुरक्षित भविष्य योजना" के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का अनुरक्षण करने और समय-समय पर इसे अद्यतन करने के लिए तंत्र विकसित नहीं किया, जिसके कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 12.66 करोड़ के प्रीमियम का अधिक भुगतान हुआ।

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा (विभाग) ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के कल्याण हेतु एक सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना "सुरक्षित भविष्य योजना" (योजना) शुरू की (1 जनवरी 2008)। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बचत के साथ-साथ बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक मास्टर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए (02 जून 2008)।

सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिकाएं, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक न हो और जिन्होंने 01 जनवरी 2008 (प्रारंभ तिथि) तक कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र थी। शेष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिकाएं, जिन्होंने 01 जनवरी 2008 तक एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी, वे प्रारंभ तिथि, 1 अप्रैल/1 जुलाई/1 अक्तूबर/वार्षिक नवीनीकरण तिथि के बाद योजना में भाग लेने के लिए पात्र थी, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा एक वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि के साथ या उसके तुरंत बाद की तिथि के साथ मेल खाती थी। मास्टर प्रस्ताव के नियम 7(iii) के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय को सदस्यों को जोड़ने/हटाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को तिमाही रिटर्न प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी।

योजना के अंतर्गत, विभाग को प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका के लिए ₹ 100[25] के मासिक प्रीमियम का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर माह में तिमाही आधार पर करना था, जो प्रवेश तिथि से शुरू होकर अंतिम तिथि[26] तक देय था। योजना के अनुसार, मृत्यु के अलावा सेवा की अंतिम तिथि या समय से पहले समाप्ति पर, सदस्य के खाते में जमा की गई कुल राशि ब्याज सहित देय थी। इसके अतिरिक्त, अंतिम तिथि से पहले मृत्यु के मामले में, सदस्य के खाते में जमा की गई कुल राशि के साथ-साथ ब्याज सहित ₹ 50,000[27] का जीवन बीमा लाभ देय था। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 31 अगस्त 2013 को इस शर्त के साथ वापस ले लिया गया था कि 01 जनवरी 2014 के बाद नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को इस योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2023) कि विभाग द्वारा निदेशालय स्तर पर और साथ ही क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों अर्थात जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) में योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने अधिकारियों/कर्मचारियों

---

25 ₹ 83 (बचत भाग) + ₹ 17 (जोखिम भाग)

26 वह तिथि जिस दिन सदस्य अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु, जो कि 60 वर्ष है, पूरी कर लेता है।

27 जुलाई 2009 से जीवन बीमा लाभ को संशोधित कर ₹ 51,000 कर दिया गया।

को पात्र सदस्यों की उचित सूची का अनुरक्षण करने का निर्देश दिया था (मार्च और सितंबर 2017), हालांकि, अनुपालन की निगरानी नहीं की गई थी। इसके बाद, विभाग द्वारा मांगी गई पात्र सदस्यों की सूची (दिसंबर 2020, जुलाई 2021 और अगस्त 2021) जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा इसे प्रदान नहीं की गई थी। इसने इंगित किया कि विभाग ने अपने क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों से लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का सत्यापन नहीं किया था। तदनुसार, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का पता लगाए बिना, पिछले वर्षों में किए गए बीमा प्रीमियम के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा था।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने विभाग को सूचित किया (दिसंबर 2021) कि अभिलेख के अनुसार, आरंभ में इस योजना के अंतर्गत 32,449 लाभार्थी शामिल थे, जो अगले वार्षिक नवीनीकरण में बढ़कर 33,634 लाभार्थी हो गए और अगस्त/सितंबर 2021 में समीक्षा के बाद, 1,531 मामलों में परिपक्वता और मृत्यु दावों के पारित होने के कारण अगस्त 2021 तक घटकर 32,103 रह गए। तथापि, अगस्त 2013 के बाद की तिमाहियों (अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा योजना को वापस लेना) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विभाग ने अक्तूबर 2013 से जून 2021 के दौरान 46,641 से 48,599 लाभार्थियों के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान जारी रखा था और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों के उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर समीक्षा के बाद जुलाई 2021 से लाभार्थियों की संख्या घटाकर 22,311 (मार्च 2022 में भुगतान किया गया) के लिए भुगतान करना शुरू कर दिया था। तदनुसार, विभाग ने अक्तूबर 2013 से जून 2021 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 12.66 करोड़[28] के बीमा प्रीमियम का अधिक भुगतान किया था, जैसा कि ***तालिका 2.3*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.3: अक्तूबर 2013 से जून 2021 के दौरान भुगतान किए गए अधिक जीवन बीमा प्रीमियम का विवरण

(₹ लाख में)

लागू अवधि	लाभार्थियों की संख्या		भारतीय जीवन बीमा निगम को		अधिक भुगतान
	जिनके प्रीमियम का भुगतान किया गया था	भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिलेख के अनुसार	किया गया भुगतान	देय भुगतान	
	(2)	(3)	(4)=माह*(2)*100	(5)=माह*(3)*100	(6)=(4)-(5)
अक्तूबर 2013 से मार्च 2014	46,641	33,634	279.85	201.80	78.05
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	48,599		583.19	403.61	179.58
अप्रैल 2015 से मार्च 2016	48,599		583.19	403.61	179.58
अप्रैल 2016 से दिसंबर 2016	48,599		437.39	302.71	134.68
जनवरी 2017 से मार्च 2017	48,504		145.51	100.90	44.61
अप्रैल 2017 से सितंबर 2017	48,504		291.02	201.80	89.22
अक्तूबर 2017 से मार्च 2018	48,428		290.57	201.80	88.77
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	48,428		581.14	403.61	177.53
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	48,428		581.14	403.61	177.53
अप्रैल 2020 से मार्च 2021[29]	48,428		476.10	403.61	133.14
अप्रैल 2021 से जून 2021	48,428		145.28	100.90	44.38
	कुल		**4,394.38**	**3,127.96**	**1,266.42**

[28] विभाग द्वारा किए गए भुगतान और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार लाभार्थियों के बीच अंतर पर गणना की गई राशि।

[29] जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक 35010 लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया गया।

इस प्रकार, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का अनुरक्षण करने और समय-समय पर इसे अद्यतन करने के लिए एक तंत्र विकसित करने में विभाग की अक्षमता, योजना के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 12.66 करोड़[30] के प्रीमियम का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बताया (सितंबर 2023, मई 2024 और अक्तूबर 2024) कि यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम के समक्ष उठाया गया था तथा उसने अतिरिक्त भुगतान से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के बाद प्रीमियम की अतिरिक्त राशि वापस करने पर सहमति व्यक्त की। विभाग ने आगे बताया (जनवरी 2025) कि सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर वास्तविक लाभार्थियों के आंकड़ों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, डेटा का सत्यापन आज तक पूरा नहीं हुआ है और इसलिए, भारतीय जीवन बीमा निगम से वसूली अभी भी प्रतीक्षित थी (जुलाई 2025)।

मामला आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग के पास भेजा गया था (सितंबर 2024); उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार (क) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का अनुरक्षण करने में उनकी विफलता और वास्तविक लाभार्थियों के सत्यापन के बिना बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे, (ख) संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ डेटा का सत्यापन करने और भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को वसूल करने के लिए उचित निर्देश जारी करे।

[30] भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए मौजूदा लाभार्थियों के आंकड़ों के अनुसार, जो विभाग द्वारा वास्तविक लाभार्थियों के सत्यापन पर भिन्न हो सकते हैं।